

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 788/2013/श्रीगंगानगर.
2. अपील संख्या - 789/2013/श्रीगंगानगर.
3. अपील संख्या - 790/2013/श्रीगंगानगर.
4. अपील संख्या - 791/2013/श्रीगंगानगर.

मैसर्स धनीराम रामचन्द्र, सूरतगढ़.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स टैक्स, श्रीगंगानगर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09/04/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपरोक्त चारों अपीलों उपायुक्त (अपीलार्थी), वाणिज्यिक कर, श्रीगंगानगर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित किये गये आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से सहायक आयुक्त / वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, श्रीगंगानगर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा पारित किये गये आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-

अपील संख्या	अपीलीय अधिकारी का		क.नि. आदेश दिनांक
	अपील क्रमांक	आदेश दिनांक	
1	2	3	4
788/2013	46/आरवैट/सूरतगढ़/2012-13	15.02.2013	27.01.2012
789/2013	468/आरवैट/सूरतगढ़/2011-12	07.02.2013	25.07.2011
790/2013	45/आरवैट/सूरतगढ़/2012-13	15.02.2013	27.01.2012
791/2013	467/आरवैट/सूरतगढ़/2011-12	07.02.2013	25.07.2011

2. इन चारों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान निहित होने से सभी प्रकरणों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उनके अवार्डर मैसर्स बी.जी.आर. एनर्जी सिस्टम लिमिटेड द्वारा काली सिन्ध थर्मल पावर प्रोजेक्ट के निर्माण में एक राइ-कॉन्ट्रेक्टर के रूप में थर्मल पावर पर Raw Water Reservoir Pond बनाये जाने हेतु सिविल कार्य करने का ठेका

लगातार.....2

दिया गया था व अपीलार्थी ठेकेदार द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-80 दिनांक 11.08.2006 के तहत सिविल कार्यों में माल के हस्तान्तरण पर विक्रय करने से मुक्ति प्राप्त करने हेतु मुक्ति शुल्क प्रमाण-पत्र का आवेदन किया गया था। अधिसूचना में मुक्ति शुल्क निम्नानुसार था :-

F.12(63)FD/Tax/2005-80

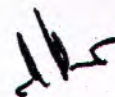
Dated : 11.08.2006

In exercise of the power conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts from payment of tax the registered dealers engaged in execution of works contracts leviable on the transfer of property in goods (Whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract(s) subject to the following conditions, namely:-

- (1) that in case of works contracts,
 - (i) awarded on or after 01.04.2006, the contractor shall apply in form WT-1; and
 - (ii) where the contractor opted for automatic exemption fee under rule 12 of Rajasthan Sales Tax Rules, 1995 **shall apply** for exemption under this notification for the remaining part of the contract as on April 1, 2006, in form WT-2.
- (2) that application **shall be submitted "within 60 days"** from the date of award of the contract or the date of issue of this notification, whichever is later;
- (3) that in case of delayed submission of the application, the assessing authority may, after recording reasons for doing so, condone the delay, on payment of a late fee of rupees one thousand for a year or part thereof. [However, delay in case of second year or part thereof can be condoned on payment of a late fee of rupees five thousand and no application shall be entertained after expiry of two year from the date of the award of the contracts].
- (4) that on receipt of the application under clause (1), the assessing authority on being satisfied as to the correctness of the facts mentioned therein, shall issue exemption certificate in Form WT-3 appended hereto, in the case of works contracts awarded on or after 1.4.2006 and in Form WT-4 appended hereto, in the case of work contracts, where the contractor opted for automatic exemption fee under rule 12 of Rajasthan Sales Tax Rules, 1995 for exemption, for the remaining part of the contract as on 01-04-2006. A copy thereof, shall be sent to the awardee.

लगातार.....3

- (5) that such contractor shall pay exemption fee at the rate specified in Column 3 of the list given below in the following manner :-
- (i) where an awarder is a Department of any Government, a Corporation, a public undertaking, a co-operative society, a local body, a statutory body, an autonomous body, a trust or a private or public limited company, an amount calculated at the rate as specified in column no.3 of the list given below shall be deducted by such awarder from each bill of payment to be made in any manner to such contractor and all the provisions of payment of tax provided in the Act or the rules made there under for contractors shall *mutatis mutandis* apply. In case the contractor has already received some payments for execution of works contract from the awarder before filing application, he shall enclose proof of payment/deduction of notified exemption fee on such payments, along with interest, if any, up to the date of filling of application, under this notification;
 - (ii) where the awarder is not covered under sub-clause (i) above, the contractor shall be required to make payment of exemption fee in equal monthly installments in a period not exceeding the period of contract from the date of filing of application. In case the contractor has already received some payments for execution of works contract from the awarder, he shall enclose proof of payment of notified exemption fee on such payment along with interest up to the date of filing of application, under this notification;
 - (iii) the amount already deducted by the awarder in lieu of tax from bills of payments to the dealer before the issuance of this notification shall be adjusted against the exemption fee;
- (6) that the contractor shall not be entitled to claim input tax credit in respect of the goods used in execution of the works contract for which exemption certificate has been granted;
- (7) that the certificate of exemption shall be liable to be cancelled by the assessing authority retrospectively if it is found that the same has been issued under contravention of the provisions of the Act, rules or notifications; and
- (8) that the tax collected or charged, if any, by such dealer before the issue of this notification shall be deposited, to the State Government and tax so deposited shall not be refunded or adjusted against the exemption fee.



Item No.	Description of work contract	Rate of exemption fee % of the total value of the contract
1	2	3
1.	Works contracts relating to dyeing, printing, processing and similar activities.	0.25 %
2.	Works contracts relating to buildings, roads, bridges, dams, canals, sewerages system.	1.50 %
3.	works contract relating to installation of plants & machinery including PSPO, water treatment plant, laying pipeline with material.	2.25 %
4.	Any other kind of works contract not covered by item No.1, 2 and 3.	3.00 %

This notification shall be deemed to have come into force w.e.f. April 1, 2006

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन अनुसार घोषित संविदा कार्य उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 2 के आईटम में कवर होना दर्शाते हुए 1.5 प्रतिशत की मुक्ति शुल्क निर्धारित करते हुए प्रमाण-पत्र क्रमशः दिनांक 14.9.2010 व 14.10.2010 जारी किये गये थे। उसके पश्चात् अपीलार्थी के आवेदित कार्यादेशों की जांच की जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जिस संविदा कार्य हेतु मुक्ति शुल्क प्रमाण-पत्र का आवेदन किया गया था, वह भवन निर्माण से सम्बन्धित कार्य न होकर सामान्य सिविल कार्य का कार्यादेश था क्योंकि उसमें थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट में काम आने वाले Raw Water Reservoir बनाने के लिये सिविल वर्क करने का आदेश दिया हुआ था, जिसके लिये बजरी, सीमेंट, सरिया आदि का उपयोग किया जाना था परन्तु वह कार्य बिल्डिंग से सम्बन्धित नहीं था, बल्कि अन्य कार्य होने से उसपर अधिसूचना की क्रम संख्या 4 के अनुसार 3 प्रतिशत से मुक्ति शुल्क देय था। इस तरह व्यवहारी के आवेदन अनुसार जारी किये गये मुक्ति शुल्क प्रमाण-पत्र को संशोधित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 3 प्रतिशत मुक्ति शुल्क जमा कराने के आदेश दिये गये एवं उसी अनुसार कर निर्धारण करते हुए मांगपत्र जारी किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की जाने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलें अस्वीकार करते हुए यह अवधारित किया गया कि अपीलार्थी को जो मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये थे वह त्रुटिपूर्ण थे, क्योंकि 'जी' शिड्यूल एवं कार्यादेश के अनुसार अपीलार्थी को थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट से सम्बन्धित Water Reservoir का निर्माण करना था जबकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में गलत रूप से बिल्डिंग कार्य बताया गया था। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

लगातार.....5

4. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।

5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रथम बार जो मुक्ति शुल्क प्रमाण-पत्र जारी किये गये थे, उसमें उनके कार्य को बिल्डिंग कार्य मानते हुए 1.5 प्रतिशत से शुल्क दिया जाना निर्धारित किया गया था, जिसमें कोई त्रुटि नहीं थी, अतः उसका संशोधन करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो विवादित आदेश पारित किये गये हैं वह विधि के विरुद्ध हैं। उन्होंने कथन किया कि एक बार मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के पश्चात् उसे संशोधित नहीं किया जा सकता एवं यह वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधन के प्रावधान में सम्मिलित योग्य नहीं है।

6. इसके अलावा विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा जो सिविल कार्य थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिये किया गया था, उसमें सीमेंट, बजरी व आयरन स्टील का प्रयोग किया गया था एवं इसमें Earth work एवं Foundation work भी था जो Civil nature का कार्य है एवं बिल्डिंग कार्य के लिये भी इसी तरह की सामग्री का प्रयोग किया जाता है, अतः इस सिविल कार्य को बिल्डिंग का कार्य ही माना जाना विधिसम्मत था।

7. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय आदेशों में कोई त्रुटि नहीं है क्योंकि कर से मुक्ति प्राप्त करने हेतु जो प्रमाण-पत्र जारी किये गये थे वे बिल्डिंग कार्य किये जाने के आवेदन को स्वीकार करने के फलस्वरूप त्रुटिपूर्ण रूप से 1.5 प्रतिशत की मुक्ति शुल्क दर दर्शाते हुए जारी किये गये थे, जबकि यह दर केवल बिल्डिंग कार्य के लिये ही लागू योग्य थी, जबकि अपीलार्थी का कार्य किसी बिल्डिंग से सम्बन्धित न होकर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिये किया जाने वाला सिविल कार्य था, जिसमें बिल्डिंग का कोई निर्माण नहीं किया गया था एवं न ही बिल्डिंग से सम्बन्धित कोई कार्य था।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

9. प्रकरणों में अपीलार्थी की ओर से दो बिन्दुओं पर तर्क प्रस्तुत किये गये हैं; प्रथमतः यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी द्वारा करमुक्ति प्रमाण-पत्र हेतु प्रथमतया दिये गये आवेदन की जांच के पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे बिल्डिंग कार्य मानते हुए 1.5 प्रतिशत की दर से शुल्क जमा कराये जाने का आदेश दिया गया था, उसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं थी एवं पूर्ण जांच

के बाद किये गये आदेशों को वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह रेकॉर्ड से परिलक्षित भूल नहीं है। इस बिन्दु पर यह निर्णय दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा जो आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया था उसमें इस कार्य को बिल्डिंग कार्य बताते हुए 1.5 प्रतिशत से मुक्ति शुल्क प्रमाण-पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया था परन्तु रेकॉर्ड पर रखे गये वर्क कॉन्ट्रैक्ट की जांच पर यह त्रुटि स्पष्ट परिलक्षित हुई कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट किसी बिल्डिंग कार्य के लिये जारी नहीं किया गया था, बल्कि उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट में अवार्डर द्वारा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट निर्माण के दौरान आवश्यक Raw Water Reservoir के लिये सिविल वर्क किया जाना था। इस तरह बिल्डिंग से सम्बन्धित कोई कार्य अपीलार्थी द्वारा नहीं किया गया है एवं न ही अवार्डर द्वारा किसी तरह का कोई बिल्डिंग कार्य किया जा रहा था। इस तरह अपीलार्थी का कार्य Relating to building work नहीं था। यह टिप्पणी करना उचित होगा कि किसी बिल्डिंग के निर्माण के दौरान बिल्डिंग से सम्बन्धित कोई अन्य कार्य किया जाता है तो वह Relating to building होने में सम्मिलित किया जा सकता है जबकि इस प्रकरण में अवार्डर द्वारा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाना था जिसमें बिल्डिंग का कोई कार्य नहीं था बल्कि उस पॉवर प्रोजेक्ट के लिये आवश्यक सिविल निर्माण कार्य अपीलार्थी द्वारा किया गया है। यह बिल्डिंग कार्य न होने से इसे अधिसूचना के आईटम नं० 2 के अनुसार 1.5 प्रतिशत शुल्क देने के स्थान पर आईटम संख्या 4 के अनुसार अन्य कार्य के रूप में 3 प्रतिशत से ही शुल्क दिया जाना था, जो स्पष्ट रूप से रेकॉर्ड से परिलक्षित भूल है क्योंकि ऐसे मामले में किसी भी तरह के तथ्यों की जांच की आवश्यकता नहीं थी बल्कि दिये गये कार्य अनुसार ही मुक्ति शुल्क की दर प्रमाण-पत्र में दर्शाई जानी थी, जो त्रुटिपूर्ण दर्शाई जाने से उसे संशोधित किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

10. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान अपीलीय अधिकारी को यह बताया गया था कि संशोधन करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मैसर्स रमेश कुमार बंसल कॉन्ट्रैक्टर का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के जिस निर्णय का हवाला दिया गया था वह निर्णय इस प्रकरण में लागू नहीं होता है। अपीलार्थी का यह कथन भी तथ्यों के विरुद्ध है क्योंकि राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 2196/2008 एवं 2199/2008 के मामले में वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स टैक्स, श्रीगंगानगर बनाम रमेश कुमार बंसल कॉन्ट्रैक्टर श्रीगंगानगर में दिये गये निर्णय दिनांक 03.02.2010 में यह विधिक निर्णय किया गया था कि "मुक्ति शुल्क" के मामले में गलत दर से मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी

लगातार.....7




किया जाना रेकॉर्ड से परिलक्षित भूल की श्रेणी में आता है एवं कर बोर्ड के उस आदेश की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गयी है, अतः संशोधन करने की अधिकारिता उक्त निर्णय से हो जाने से अपीलार्थी का तर्क खारिज किया जाता है।

11. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा गुणावगुण पर यह कथन किया गया है कि उनके द्वारा जो कार्य संविदा की गयी है, वह अधिसूचना के आईटम नं० 2 के अनुसार बिल्डिंग की श्रेणी में आती है क्योंकि बिल्डिंग कार्य में सीमेंट, बजरी एवं आयरन स्टील का प्रयोग होता है एवं उनके द्वारा किये गये कार्य में भी सीमेंट, बजरी का प्रयोग हुआ है, अतः इन्हें एक ही प्रकृति का मानते हुए उनके कार्यों को बिल्डिंग के रूप में माना जाना चाहिये था। यह तर्क भी तथ्यों एवं विधि के विरुद्ध है क्योंकि पत्रावली पर उपलब्ध वर्क ऑर्डर में अवार्डर बी. जी.आर. एनर्जी सिस्टम लिमिटेड द्वारा उनके थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट पर सिविल कार्य करने का कार्यादेश उक्त अपीलार्थी को दिया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से foundation work एवं अन्य कार्य, जो कि उनके थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिये Raw water reservoir के निर्माण में आवश्यक थे, उसके निर्माण का आदेश दिया गया था, जिसमें बिल्डिंग कार्य का कोई सम्बन्ध नहीं था एवं न ही कार्यादेश में कोई बिल्डिंग बनाये जाने का सन्दर्भ दिया हुआ है। इस तरह अपीलार्थी का कार्य उक्त अधिसूचना के अनुसार बिल्डिंग कार्य से सम्बन्धित न होकर Thermal Power Project से सम्बन्धित सिविल कार्य होने से उस पर उक्त अधिसूचना अनुसार 3 प्रतिशत से ही शुल्क देय है।

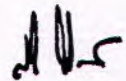
12. फलतः गुणावगुण पर भी अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित उक्त समस्त संशोधन आदेश एवं अपीलीय आदेश विधिसम्मत पाये जाते हैं।

13. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलें अस्वीकार की जाकर, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किये गये संशोधित आदेश एवं अपीलीय आदेशों की पुष्टि की जाती है।

14. निर्णय सुनाया गया।



(के. एल. जैन)
सदस्य



(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष